

रजिस्टर्ड नं ० पी०/एम०एम० १४.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १० सितम्बर, १९८३/१९ भाद्रपद, १९०५

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-1, the 20/21st August, 1983

No. Agr. F. 12-1/81.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate the Secretary Science and Technology to the Government of Himachal Pradesh as member on the State level crop weather watch group constituted *vide* this Department notification of even number dated 16-10-1981.

By order,
B. C. NEGI,
Financial Commissioner.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सी शाखा)

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अगस्त, 1983

संख्या 3-40/73-(II).—इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी०ए०डी० (जी०आई०) 6 (एफ) 12/77 जी०ए०सी०दिनांक 23-2-80 के संदर्भ में, जिसके अन्तर्गत तहसील चॅप्टर के मुख्यालय को थुनाग में स्थानान्तरित किया था, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, अब इस तहसील का नाम तहसील थुनाग रखने का तत्काल सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
आयुक्त एवं सचिव।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th April, 1983

No. 7-5/70-Home (B)-Jud. V.—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the High Court of Himachal Pradesh and the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 1973, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Service (1st Amendment) Rules, 1983.

(ii) They shall come into force with effect from the date of issue of this notification.

2. *Amendment in sub-rule (5) of rule 5 of Part III-B.*—Note (i) of sub-rule (5) of rule 5 of Part III-B of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 1973 containing the provision “Bare copies of legislative enactments only will be supplied” shall be deleted and notes (ii) and (iii) shall be renumbered as (i) and (ii) respectively.

I. K. SURI,
Special Secretary.

श्रम, रोजगार एवं मुद्रण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 22/25 अगस्त, 1983

सं० 7-15/83-एल ०ई०पी०:—यत. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ईंट भट्टा उद्योग के रोजगार का न्यूनतम वेतन दर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित किया जाए;

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि उक्त रोज़गार को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में जोड़ा जाए;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 27 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि ईंट भट्टा उद्योग के रोज़गार को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में जोड़ा जाए। प्रभावित व्यक्ति यदि कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव अमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को दे दें। तत्पश्चात् यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त हुये तो उन पर इस सरकार द्वारा विचार करने के पश्चात् अनुसूची को हिमाचल प्रदेश में लागू होने की स्थिति में ऐसी ही अधिसूचना द्वारा संशोधित समझा जाएगा।

[Authoritative English text of this Government Notification No. 7-15/83 dated 22-8-83 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India]

LABOUR EMPLOYMENT, PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 22/25th August, 1983

No. 7-15/83-LEP.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that minimum rates of wages in respect of employment in brick-kiln industry should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948;

And whereas the Governor, Himachal Pradesh intends to add the employment in brick-kiln industry to Part-I of the Schedule to the Minimum Wages Act, 1948;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) gives notice of his intention to add the employment in brick kiln industry to Part-I of the schedule to the said Act. Interested person may give objections/suggestions in this behalf to the Labour Commissioner, H. P. before the expiry of three months from the publication of the notification in the Rajpatra, H. P. whereafter the objections/suggestions if any, will be considered by the Government and the scheduled shall in its application to the State of H. P. be deemed to be amended by like notification.

शिमला-171002, 23/26 अगस्त, 1983

संख्या 4-13/83-थ्रम.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि “कपड़ा तथा बुनाई उद्योग रोज़गार” के न्यूनतम वेतन दर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित किए जाएं;

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि उक्त रोज़गार को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में जोड़ा जाए।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या-11) की धारा 27 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि “कपड़ा तथा बुनाई उद्योग रोज़गार” को उक्त अधिनियम की अनुसूचि के भाग-1 में जोड़ा जाए। प्रभावित व्यक्ति यदि कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर अपनी

आपत्ति ग्रयवा सुझाव श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को दें। तत्पश्चात् यदि कोई सुझाव ग्रयवा आपत्ति प्राप्त हुए तो उन पर इस सरकार द्वारा विचार करने के पश्चात् अनुसूची को उसकी हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू होने की स्थिति में से ही अधिसूचना द्वारा संशोधित समझा जाएगा।

[Authoritative English text of this Government Notification No. 4-13/83-Shram dated 23-8-1983 as required under article 348 (2) of the Constitution of India]

Shimla-2, the 23/26th August, 1983

No. 4-13/83-Shram.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that minimum rates of wages in respect of "employment in Textile and Hosiery Manufacture Industry" should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948.

2. And whereas the Governor, Himachal Pradesh intends to add the "employment in Textile and Hosiery Manufacture Industry" to Part-I of the schedule to the Minimum Wages Act, 1948.

3. Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) gives notice of his intention to add the employment in Textile and Hosiery Manufacture Industries to Part-I of the schedule of the said Act. Interested persons may give objections/suggestions in this behalf to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-2, before the expiry of three months from the publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh whereafter the objections/suggestions if any, will be considered by the Government and the schedule shall in its application to the State of Himachal Pradesh be deemed to be amended by like notification.

शिमला-171002, 26 अगस्त, 1983

मंख्या 8-3/82-एल 0 ई 0 री 0.—यतः इस विभाग की अधिसूचना सम संख्या दिनांक 16-12-82 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश दिनांक 15-1-83 में प्रकाशित हुई थी, चाय बागान में काम कर रहे अकुशल कर्मचारियों/मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित किए गए थे;

और यतः चाय बागान में काम कर रहे अकुशल मजदूरों को मालिकों द्वारा दी गई अन्य सुविधाओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होती है कि चाय बागान में काम कर रहे अकुशल कर्मचारियों/मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर पुनः निर्धारित किये जायें।

और यतः उपरोक्त व्यवसाय में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 को उम्मीदारा (1) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत प्रदत्त जकियों का प्रयोग करते हुए और न्यूनतम वेतन सलाहकार बॉर्ड के परामर्श पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल चाय बागान में काम कर रहे अकुशल कर्मचारियों/मजदूरों के दैनिक मजदूरी दर रूपय 7/- नियत करने परं निम्नलिखित स्थानों पर उसके सामन दिखाई गई बढ़ीतरी के प्रस्ताव को प्रकाशित करने के

तुरन्त सहर्ष आदेश देते हैं।

स्थान	वटीनगरी
1. जिला नाहोल-सिपति, किन्नौर तहसील, भरमौर तथा तहसील पांगी, जिला चम्बा	25 प्रतिशत
2. मनाना ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू	
3. डोडरा क्वार, तहसील रोहड़, जिला शिमला	
4. छोहरा बैली, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी	
5. बड़ा बंगाल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा	
1. तहसील परागपुर तथा तहसील चौपाल, जिला शिमला	20 प्रतिशत
2. तहसील आनी तथा निरमंड, जिला कुल्लू	
3. ग्राम पंचायत मांगल, जिला सोलन	
4. चवासी इलाका, तहसील करसोग, जिला मण्डी	
5. गेरवी देहात तथा बड़ोवारा, तहसील मुन्दरनगर, जिला मण्डी	
1. तहसील रोहड़, जिला शिमला (डोडरा क्वारको छोड़कर)	12½ प्रतिशत
2. सब-तहसील शिलाई, रेणुका तहसील, जिला सिरमौर	
3. तहसील चुराह, जिला चम्बा	
4. इलाका मनाली तथा यूहजी पार्वती तथा लाग बैली, बन्जार	
ब्लाक, कुल्लू, जिला कुल्लू	
5. कुट पंचायत तथा परगना बेलाज, जिला चम्बा	
6. झंझाली ब्लाक, तहसील चंचोट, जिला मण्डी	
7. तहसील करसोग, जिला मण्डी (इलाका चवासी को छोड़कर)	

नोट—1. उपरोक्त दर समस्त दरों को मिलाकर है।

2. महिला तथा पुरुषों को समान मजदूरी दी जाएगी।

प्रभावी होने वाले व्यक्तियों को एतद्वारा सचित निया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर विवार इस अधिसूचना के राजनीति हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की विधि के दो मह के पश्चात् किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव से संबंधित सभी आपत्तियां तथा सुव्यावधारणायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेजे जावें।

आदेश द्वारा,
राजेन्द्र कुमार आनन्द,
सचिव।

श्रम विभाग
अधिसूचना

शिमला-171002, 29 अगस्त, 1983

संख्या 8-12-81-श्रम.—यह: हिमाचल प्रदेश के रज्यान को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अनेकित है कि हिमाचल पश्चिम परिवहन नियम की सेवाओं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं० 14) की प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हतु जन उपयोगी सेवाएं घोषित करना चाहिए;

श्रीर यह: उक्त सेवाएं अधिसूचना संख्या 8-12-81-श्रम, दिनांक 7-2-1983 जो हिमाचल राजपत्र दिनांक 26-2-83 असाधारण में प्रकाशित हुई थी, द्वारा 6 मर्टीनों के लिए जन उपयोगी सेवाएं घोषित की गई थी;

और यह: राज्यपाल, हि० प्र० को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं का जन उपयोगी सेवाकाल छः महीने तक घोषित करना अनिवार्य है।

ग्रन्त: ग्रामीणिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप-खण्ड (vi) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवाकाल उक्त अधिनियम के प्रयोगन हेतु छः मास तक की अवधि के लिए सहर्ष तुरन्त घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (श्रम) ।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 18 अगस्त, 1983

संख्या 1-6/76-परिवहन:— समसंबद्धक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर, 1982 का अधिकमण करते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त धारा की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों के सारे राज्य में प्रयोग और निर्वहन हेतु निम्नलिखित रूप में राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करते हैं:—

सरकारी सदस्य:

- वित्तायुक्त, हिमाचल प्रदेश (रैवेन्यु)
- आयुक्त परिवहन, हिमाचल प्रदेश
- इन्सपैक्टर जनरल पुलिस, हिमाचल प्रदेश
- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण

चेयरमैन
सदस्य
सदस्य
पदेन सदस्य सचिव

गैर सरकारी सदस्य :

- श्री धर्मवीर, ग्राम तथा डाकखाना सिमुभाग, कुलू
- श्री मनजीत डोगरा, ग्राम अम्बारी, डाकखाना मौलान, तहसील तथा ज़िला कांगड़ा
- श्री सागर चन्द नैयर विधायक
- श्री पीरु राम विधायक
- श्री मोती राम विधायक
- डा० प्रेम सिंह विधायक
- श्री गुनावं सिंह विधायक
- श्री मत्यपाल गुप्ता, एडवोकेट, नूरपुर
- श्री देव राज नेगी, 6, दि माल, शिमला
- पंडित हरि राम, भूतपूर्व विधायक, रामा न्यूज एजेन्सी, शिमला
- श्री गोपाल चन्द नेगी, १ ला किन्नौर
- श्री देवी दाम मैहता, ग्राम जगुणी, ३० ढांसा, तहसील रामपुर
- श्री सत्यदेव वुशंहरी विधायक

14. श्री किशोरी लाल टाड़, भूतपूर्व विधायक, विलासपुर	मदस्य
15. श्री धनी राम विधायक	मदस्य
16. श्री अमर नाथ विजवाड़िया, डा० देहरा गोपीपुर, ज़िला कांगड़ा	मदस्य
17. श्री दयाल दत्त शर्मा, ग्राम तथा डा० ओचबाट, ज़िला सोलन	मदस्य
18. श्री किशोरी लाल, उप-प्रधान वैजनाथ	मदस्य
19. श्री ज्ञान चन्द मिनहास, भूतपूर्व विधायक	मदस्य

2. उपरोक्त विधान सभा सदस्यों की सदस्यता केवल एक वर्ष के लिए होगी ।

3. राज्य परिवहन प्राधिकरण के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता वाद में निर्धारित किया जाएगा ।

आर० के० आनन्द,
मन्त्रिव (परिवहन) ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 1983

संख्या ए.ल. एस. जी. सी. (9)38/75.—हिमाचल प्रदेश न्यूनिसिपल एक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 60 और 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उनकी पूर्व स्वीकृति सहित, अधिसूचित क्षेत्र ज्वालामुखी, ज़िला कांगड़ा को अपने क्षेत्रीय अधिकारिता में भरे हुए ट्रकों, बसों, कारों, जीपों, टैम्पो और लाइट वाहनों के होने पर प्रवेश होने पर प्रवेश शुल्क निम्नलिखित दरों से आरोपित किया है, को सहर्ष अधिसूचित करते हैं :—

1. भरे हुए ट्रक और बस	5 रुपये प्रति प्रवेश
2. कार, जीप, टैम्पो और लाइट वाहन	3 रुपये प्रति प्रवेश :

परन्तु यदि वाहन 24 घण्टे के अन्दर पुनः अधिसूचित क्षेत्र ज्वालामुखी में प्रवेश कर जावे तो उससे दोबारा प्रवेश शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

2. यह शुल्क प्रथम अक्टूबर, 1983 से लागू होगा ।

[Authorised English text of Notification No. LSGC(9) 38/75 dated 23-8-1983 is published under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, for information of the public].

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd August, 1983

No. LSGC(9)-38/75.—In exercise of the powers conferred by sections 60 and 61 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that with his prior approval, the Notified Area Committee, Jwalamukhi, Kangra district, has imposed the entry fee on the loaded trucks, buses, cars,

jeeps, tampos and light vehicles entering within its territorial jurisdiction at the following rates:—

(i) Loaded trucks and buses	Rs. 5/- per entry;
(ii) Car, jeep, tambo and light vehicles	Rs. 3/- per entry;

Provided that if a vehicle re-enters the territorial jurisdiction of Notified Area Committee, Jawalamukhi again within 24 hours, the entry fee will not be charged again.

2. This fee shall come into force with effect from 1st October, 1983.

By order,
A. K. GOSWAMI,
Secretary.

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 3rd August, 1983

No. EDN-II (TEA)(3)4/74-II.—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to frame and notify the Recruitment & Promotion Rules in respect of Class I (Gazetted) post of Lecturer in Architecture in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training as per Annexure to this notification.

These rules shall come into force from the date of issue of this notification.

C. P. SUJAYA,
Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF LECIURER IN ARCHITECTURE IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING

1. Name of post	Lecturer in Architecture.
2. Number of posts	2 (Two).
3. Scale of pay	Rs. 940-1850 plus Rs. 100/- special pay p. m. with two advance increments for Post-Graduates.
4. Classification	Class-I Gazetted.
5. Whether selection post or non-selection post.	Selection.
6. Age for direct recruits.	30 years and below.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential: At least Second Class Bachelor's Degree in Architecture from a recognised University or equivalent.

Desireable:

	(i) Two years professional/teaching experience in Architecture; and
	(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of H. P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in H. P.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be reduced to writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotions, deputation/transfer to be made.	Not applicable.
12. If a DPC exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.

*Foot Notes.—*1. A candidate for appointment to any service or post must be,—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India/State Government.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India/Government of Himachal Pradesh.

2. Upper age-limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in the service of the Government.

3. Upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the H. P. Government.

4. Age-limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed for receipt of applications by the Commission.

5. Age and qualifications for direct recruits relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

6. Provisions of columns 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under column 2 are increased or decreased.

7. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

8. Selection for appointment to these posts in the case of direct recruitment, shall be made on the basis of *viva voce* test, if the Commission so considers necessary or expedient by a written test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or a practical test.

9. In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* one) in the feeder post, all persons senior to him in the respective category shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion/confirmation shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the relevant recruitment and promotion rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion/confirmation, on account of the requirement prescribed in the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion/confirmation.

10. The employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age-concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/

autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

11. The appointments to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

12. *Departmental Examination.*—(i) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules within the probation period or within two years from the notification of these rules whichever is latter failing which he shall not be eligible to—

- (a) cross the Efficiency Bar next due;
- (b) confirmation in the service; and
- (c) promotion to the next higher post:

Provided that if a member becomes otherwise eligible for promotion, within the period mentioned above, he shall be considered for promotion and if otherwise found fit, shall be promoted provisionally subject to his passing the departmental examination. He may be reverted if he fails to pass the same:

Provided further that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any other rules before the notification of these rules, shall not be required to qualify the whole or in part of the examination as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st of March, 1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules.

(ii) An officer for promotion to a higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination, if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(iii) The Government may, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced to writing, exemption in accordance with the departmental examination rules, to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।